

भीम प्रज्ञा अलर्ट

जिस दिन हम अपने अधिकारों से पहले अपने कर्तव्यों को याद रखने लगेगे, उसी दिन समाज में परिवर्तन स्वतः दिखाई देने लगेगा।

भीम प्रज्ञा

2009 से स्थापित

सम्यक, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, एवं सामाजिक चेतना के लिए रचनात्मक पत्रकारिता

गांव के गुवाड़ से निकलकर प्रकाशित होने वाले दैनिक अखबार भीम प्रज्ञा की मजबूती के लिए पाठक बनिए और बनाइए अपनी प्रतिक्रिया दीजिए

हेल्पलाइन - 9983040937

Bheem Pragya publication

A/C No: 61347330768

IFSC Code- SBIN0031880

Phone pe , G-pay

9983040937

www.bheempragya.in

वर्ष-1

अंक-83

झुंझुनू (राजस्थान)

गुरुवार, 12 फरवरी, 2026

Email.bheempragya@gmail.com

पृष्ठ-8

मूल्य: 5.00

राजस्थान

2026

बजट

इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार, सड़कें, एयरपोर्ट और पेयजल परियोजनाएं

युवाओं को रोजगार और लोन, टेस्टिंग एजेंसी का गठन

हेल्थ और महिला सशक्तिकरण, और लखपति दीदी योजना

दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदना सस्ता, होमगार्ड के 5 हजार पद बढ़ाए

8वें वेतन आयोग की तैयारी, अनुकंपा नियुक्ति के नियम बदले

कर्मचारियों, किसानों और युवाओं पर फोकस

भीम प्रज्ञा न्यूज

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट 2026-27 राजस्थान के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं-आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के तीन कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए बनाया गया है। यह बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति हमारे कर्तव्यों का दस्तावेज है। बुधवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी द्वारा राज्य बजट 2026-27 प्रस्तुत किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि अंत्योदय के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्य तिथि के दिन आया यह बजट महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान सहित अतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण को समर्पित है। उन्होंने कहा कि बजट में आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण सहित बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिससे राजस्थान विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है।

आरएसटीए से परीक्षाओं में पारदर्शिता होगी सुनिश्चित

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए बजट में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को निरंतर रोजगार प्रदान कर रही है। 5 साल में 4 लाख नौकरियों के संकल्प को पूरा करने के क्रम में अब तक 1 लाख से अधिक को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 1 लाख 54 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख का भर्ती कैलेंडर जारी किया है। वहीं, निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं।

10 स्तम्भों पर आधारित हमारा बजट

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को तेजी से पूरा कर रही है। राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में 1441 बजट घोषणाएं की थी, जिनमें से 1246 घोषणाओं (86 प्रतिशत) और वर्ष 2024-25 के बजट की 1277 घोषणाओं में से 1188 घोषणाओं (93 प्रतिशत) की क्रियान्विती की गई है। उन्होंने कहा कि बजट 2026-27 अवसंरचना का विस्तार, नागरिक सुविधाओं से गुणवत्तायुक्त जीवन स्तर में वृद्धि, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, मानव संसाधन का सशक्तीकरण, सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर, सुरासन एवं डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण, हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मजबूत स्तम्भों पर आधारित है।

राजस्थान- फ्री इलाज, किसानों को सस्ती बिजली:



प्रतिव्यक्ति आय पहली बार हुई 2 लाख रुपये से अधिक

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशल वित्तीय प्रबंधन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आया है। इस बजट के अनुमान अनुसार राज्य की जीएसडीपी 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये होना संभावित है, जो 2023-24 से लगभग 41 प्रतिशत अधिक है। वहीं, प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2 लाख 2 हजार 349 रुपये होना संभावित है, जो 2023-24 से 21.15 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय 53 हजार 978 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो 2023-24 से 2 गुना से अधिक है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32 हजार 526 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जो 2023-24 से 53 प्रतिशत अधिक है। ग्रीन बजट में 33 हजार 476 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष से 20.81 प्रतिशत अधिक है।

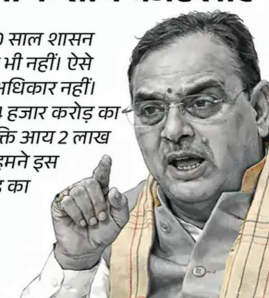
वीबी जी राम जी में 4 हजार करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में वीबी जी राम जी योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 76 लाख किसानों के खातों में 10 हजार 900 करोड़ से अधिक की राशि डेबिट की गई है। यमुना जल को शेखावाटी क्षेत्र तक लाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपये के कार्य शुरू होंगे। रामजल सेतु लिंक परियोजना में 26 हजार करोड़ रुपये के कार्यदेश जारी किए जा चुके हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी, पंचायत स्तर पर नमो पार्क और 16 जिलों में ऑक्सिजन स्थापित किए जाएंगे।

10 संकल्पों के साथ बजट लाए

विपक्ष ने इस राज्य पर 50 साल शासन किया, लेकिन किया कुछ भी नहीं। ऐसे में उन्हें सवाल पूछने का अधिकार नहीं। वीबीजी-रामजी के लिए 4 हजार करोड़ का प्रावधान किया। प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए से अधिक हो गई। हमने इस वित्त वर्ष में 8 हजार करोड़ का घाटा कम किया।

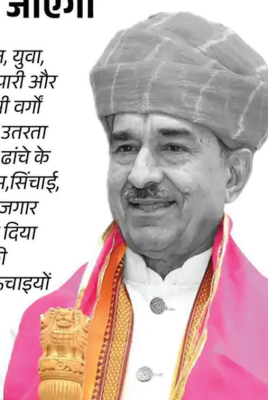
भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री



बजट नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा

बजट आमजन, किसान, युवा, महिला, कर्मचारी, व्यापारी और उद्योग जगत सहित सभी वर्गों की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। बजट में आधारभूत ढांचे के विस्तार, ग्रामीण विकास, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

मदन रावोड़
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष



सरकार को मेंटल हेल्थ चेकअप की जरूरत

बजट में कुछ नहीं था, सबसे पहले तो यह लड़ाई रहती है कि घोषणा मुख्यमंत्री करें कि वित्त मंत्री करें। बजट के दौरान इनके तीन मंत्री सो गए। लोगों को मेंटल हेल्थ चेकअप की जरूरत नहीं है। सरकार को अपना खुद का मेंटल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, सरकार के मंत्री किस स्थिति में हैं।

टीकाराम जूनी
नेता प्रतिपक्ष



जिला स्तर पर खुलेंगे रूरल महिला बीपीओ

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर रूरल महिला बीपीओ, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तथा लखपति दीदी योजना में ऋण को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख आदि प्रावधान महिलाओं के सशक्तीकरण में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खुड़ी (जैसलमेर) में अल्ट्रा लक्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। शेखावाटी हवेली योजना के अंतर्गत 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वेतनमान एवं पदोन्नति सहित विभिन्न मांगों के परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेशवासियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा सुरासन देने में कर्मिकों की महती भूमिका है। हमारी सरकार कर्मिकों व पेशनर्स के हितों के लिए संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी संगठनों द्वारा पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने व वेतनमान में संशोधन सम्बन्धी विभिन्न मांगों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुशंसा किये जाने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति भविष्य में आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे राज्य में लागू करने के सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षण कर अपनी सिफारिशों राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।



शिक्षा के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के क्रम में बजट में 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो 2023-24 से 35 प्रतिशत अधिक है। 400 स्कूल को सीएम राइज विद्यालयों के रूप में

क्रमोन्नत भी किया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। वहीं, जयपुर के जे.के. लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर तथा आरयूएचएस में 200 बेड के पीडियाट्रिक आईपीडी का प्रावधान किया है।



डेयरी मंत्री बोले- बजट विकसित राजस्थान- 2047 के लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम



डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि यह बजट विकसित राजस्थान- 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ठोस कदम है। यह बजट समृद्ध किसान, सशक्त पशुपालक और विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रावधानों से राज्य में पशुपालन क्षेत्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा- बजट में पशुपालन, डेयरी, सहकारी निवेश को लेकर जो प्रोत्साहन दिए गए हैं, वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगे। मंत्री ने इसे महिलाओं, छोटे किसानों और ग्रामीण गरीबों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान (विकसित भारत) के लिए एक निर्णायक कदम माना। कुमावत ने पशुपालन से किसानों की आय में 25 से 30 प्रतिशत योगदान को स्वीकारते हुए कहा कि इस क्षेत्र में उद्यमिता विकास और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इस बार 6.11 लाख करोड़ का बजट

इस बार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ का बजट पेश किया है। पिछली बार बजट का साइज 5 लाख 58 हजार 596 करोड़ था। इस बार बजट का साइज पिछली बार से 52 हजार 360 करोड़ ज्यादा है।

गाड़ियों पर लगेगा कम टैक्स

दीया ने कहा- सरकार ने कर्ज दस्तावेजों पर पंजीयन दर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया है।

बजट में अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों पर टैक्स में कमी की गई है।

अब सरकारी भवनों के निर्माण में 50 प्रतिशत तक एम सेंड का इस्तेमाल होगा, इसे 25 फीसदी से बढ़ाते हुए 50 प्रतिशत किया गया।

वैट, भूमि कर, खनन, परिवहन से जुड़े बकाया टैक्सों के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी।

250 डीवी चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे, 60 नए सीएनजी स्टेशन खुलेंगे।

लॉजिस्टिक सेंटर्स को भी अब रिफ-2024 का लाभ मिलेगा, कस्टमाइज पैकेज और छूट मिलेंगी।



लोकसभा-अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास: लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा



ललित गर्ग

लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका केवल कार्यवाही संचालित करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह सदन की गरिमा, लोकतांत्रिक मयार्द और सभी पक्षों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की सवैधानिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं। यदि विपक्ष का एक बड़ा वर्ग यह महसूस करने लगे कि अध्यक्ष का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है या उनकी आवाज को व्यवस्थित रूप से दबाया जा रहा है, तो यह केवल राजनीतिक असंतोष नहीं, बल्कि संस्थागत अविश्वास का संकेत होता है।



पर मजबूर करती है कि आधिप संसद जैसे सर्वोच्च मंच पर संवाद की जगह हंगामा, नारेबाजी और गतिरोध क्यों हावी होता जा रहा है। क्या यह केवल सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास का परिणाम है, या फिर संसदीय प्रणाली और के क्षरण का संकेत ? विगत वर्षों में बार-बार यह देखने को मिला है कि महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर गंभीर चर्चा के बजाय सदन की कार्यवाही बाधित होती रही है। इससे न केवल विधायी कामकाज प्रभावित होता है, बल्कि जनता के बीच यह संदेश भी जाता है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह असहमति को स्वीकार देता है। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह ठहराना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना भी है। इसके लिए सदन में बोलने का अवसर, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता और आलोचना का सम्मान अनिवार्य हैं। यदि विपक्ष यह महसूस करता है कि उसके लिए ये रास्ते संकुचित किए जा रहे हैं, तो उसका आक्रोश सड़कों या नारेबाजी के रूप में फूट पड़ता है, जो अंततः संसद की गरिमा को ही नुकसान पहुँचाता है। दूसरी ओर, विपक्ष द्वारा बार-बार सदन की कार्यवाही बाधित करना भी उसना ही गंभीर जना है, क्योंकि इससे शासन की प्रक्रिया ठप होती है और जनता के मुँदे पीछे छूट जाते हैं। इस दोतरफा अविश्वास

और आक्रामकता के बीच लोकतंत्र का मूल उद्देश्य कहीं खोता हुआ दिखता है।
दिलिबन के सबसे बड़े लोकतंत्र में यदि संसद बार-बार हंगामे, निर्गुलन और गतिधरो की खबरों में रहे, तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की लोकतांत्रिक छवि को प्रभावित करता है। विकास, नीति और जनकल्याण की चर्चा के स्थान पर यह लिए टकराव और अविश्वास केन्द्र में आ जाए, तो यह भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती केवल मजबूत सरकार से नहीं, बल्कि मजबूत विपक्ष और निष्पक्ष संस्थाओं से भी आती है। लोकसभा अध्यक्ष जैसे पद से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल नियमों का पालन करेगा, बल्कि विश्वास का सेतु भी बने। वहीं विपक्ष से भी यह अपेक्षा है कि वह विरोध की रचनात्मक बनाए, न कि अवरोध का माध्यम।
आज आवश्यकता इस बात की है कि संसद को फिर से संवाद का मंच बनाया जाए, जहाँ तीखी असहमति भी मयादा में व्यक्त हो और सत्ता व विपक्ष दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएँ। अविश्वास प्रस्ताव जैसे कदम यदि चेतावनी के रूप में लिए जा रहें हैं, तो उन्हें आत्ममंथन का अवसर भी बनना चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि संसद सही है और कौन गलत, बल्कि यह है कि लोकसभा की संस्था को कैसे स्वस्थ, विश्वसनीय और प्रभावी बनाया

सम्पादकीय



**एडवोकेट
हरेश पंवार**

Contact No.
9983040937

मैं बोलूंगा तो फिर
कहोगे कि बोलता है

**इलाज के नाम पर सच और झूठ का खेल –
जब तक चेतना नहीं, तब तक व्यवस्था नहीं**

स्वास्थ्य योजनाएं ऐसी भी अभ्यन्त समाज की संवेदनशील पहचान होती हैं। इनका उद्देश्य होता है कि अंतिम पक्षित में खड़ा स्वस्थ भी बिना भ्रम और झूठ के इलाज पा सके। लेकिन आज की खड़ा सच्चाई यह है कि इलाज और वसूली, सेवा और सौदेबाजी के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। निजी अस्पतालों में मेडिकल कर्मों का नाम पर जो कुछ चल रहा है, वह केवल व्यवस्था की कमजोरी नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का परिणाम है—जिसमें सच कम और झूठ ज्यादा है। यहां मैं बोलूंगा तो फिर कहोगे कि बोलता है। यह मान लेना कि कानून को और कठोर बना देने से, या कार्डों की प्रक्रिया को और जटिल कर देने से यह गोरखधंधा रुक जाएगा, अपने आप एक भ्रम है। कागज पर कानून जितने भी सख्त क्यों न हों, जमीन पर जब तक नीयत नहीं बदलेगी, तब तक परिणाम नहीं बदलेगा। आज समस्या केवल अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गांव-गांव फैले उन कमीन-नखोरी नेटवर्क तक पहुंच चुकी है, जो कांडेधारकों की तलाश में घूम रहा है।

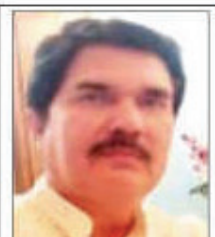
शामिणी क्षेत्रों में एक नया व्यवस्थापन पनप चुका है। दलाल, बिचौलिया और तलाक़प्रीत समाजजनों की घर-घर जाकर काउन्सिलरों को यह समझाते हैं कि इलाक़ा फ़ैस है, 'जांच करवा लो', 'अस्पताल ले चलेंगे', 'एम्बुलेंस फ़्री आएंगी'। बीमारी हो या न हो, मानसिक रूप से बीमारी का डर पैदा कर लोगों को अस्पताल की इहलीज तक पहुँचाया जा रहा है। गाँव से शहर तक एम्बुलेंस दौड़ रही हैं—मरीज कम, काउंट ज्यादा। अस्पताल पहुँचते ही यहाँ नेवर्क आगे बढ़ जाता है। वहाँ मौजूद काउन्सिलर, एजेंट और मार्केटिंग से जुड़े लोग जांचों की एक लंबी सूची धमा देते हैं। सामान्य व्यक्ति, जिसे लगता है कि जब से पैसा नहीं जा रहा है, बिना सवाल किए सब कुछ स्वीकार कर लेता है। यही वह बिंदु है, जहाँ सच इलाज पीछे छूट जाता है और झूठा इलाज आगे आ जाता है। सच यह है कि कई बार इलाज जरूरी होता है। सच यह है कि हर मरीज जांचों जाँच ज़रूरी नहीं करवा सकता है। लेकिन झूठ यह है कि हर मरीज को भर्ती करना जरूरी है। झूठ यह है कि हर जांच अनिवार्य है। झूठ यह भी है कि 'सकारा दे रही है' तो संसाधनों का दुरुपयोग कोई अपराध नहीं। यही झूठ धीरे-धीरे योजनाओं की आत्मा को खोखला कर रहा है। इस पूरी खेल में अस्पताल प्रबंधन ने मार्केटिंग की नई एजेंसियाँ खड़ी कर ली हैं। ये एजेंसियाँ मरीज नहीं, बल्कि काउंट खोजती हैं। पित्तना ज्यादा क्लेम, उतना ज्यादा मुनाफ़ा। नर्सिंग स्टाफ़, तकनीकी कर्मचारी और ज़मीनी व्यवस्थापक भी आज भी सीमित वेतन और असुरक्षित हालातों में काम कर रहे हैं, जबकि असली कमाई प्रबंधन और नेटवर्क के हाथों में सिमट जाती है। यह असमानता भी इस व्यवस्था का एक बड़ा सच है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन केवल अस्पताल और नेवर्क को दोष देना भी अधूरा सच होगा। इस व्यवस्था को चलाने में हमारी सामूहिक मानसिकता भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। जब तक आम व्यक्ति यह नहीं समझेगा कि हर जांच जरूरी नहीं, हर भर्ती फायदेमंद नहीं और हर सुविधा मुफ़्त नहीं होती—तब तक यह चक्र चलता रहेगा। जब तक लोग बिना जरूरत जांच की पर्चा नहीं लेकर, दवाइयों की थैलियाँ उठाए घूमते रहेंगे, तब तक योजनाओं का दुरुपयोग रूकने वाला नहीं है।

असल बदलाव काबू न से नहीं, मानसिक परिपक्वता से आएगा। मरीज को भी सवाल पूछने होंगे- 'यह जांच क्यों?', 'भर्ती क्यों?', 'कोई दूसरा विकल्प?'। समाज को यह समझना होगा कि योजना का उपयोग और दुरुपयोग के बीच फर्क क्या है। जरूरतमंद का हक तभी बचेगा, जब गैर-जरूरतमंद खुद पीछे हटना सीखेगा।



योगेश कुमार गोयल

आर्य समाज के संस्थापक के रूप में वंदनीय महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकारा में 12 फरवरी 1824 को हुआ था और 12 फरवरी को उनकी जयंती मनाई जाएगी। स्वामी दयानंद ऐसे देशभक्त, समाज सुधारक, मार्गदर्शक और आधुनिक भारत के महान चिंतक थे, जिन्होंने न केवल ब्रिटिश समाज से जमकर लोहा लिया बल्कि अपने काल से समाज को नई दिशा और ऊँची प्रगति की ओर 1857 की क्रांति में उनका अमूल्य योगदान था। स्वामी दयानंद का बचपन बहुत अच्छा बीता लेकिन उनके जीवन में घटी एक घटना ने उन्हें इस कदर प्रभावित किया कि वे 21 वर्ष की आयु में ही अपना घर भाग छोड़कर आत्मिक एवं धार्मिक सत्य की तलाश में निकल पड़े और एक सन्यासी बन गए। जीवन में ज्ञान की तलाश में वे स्वामी विराजाने से मिले, जिन्हें अपना गुरु मानकर उन्होंने मथुरा में वैदिक तथा योग शास्त्रों के साथ ज्ञान की प्राप्ति की। 1845 से 1869 तक कुल 25 वर्षों की अपनी साराय यात्रा में उन्होंने कई प्रकार के दैविक क्रियाकलापों का बोध विभिन्न प्रकार के योगों का भी गहन अभ्यास किया।



ڈॉ ہدایت احمد خان

बांग्लादेश में अचानक जेन-जी आंदोलन और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना अमास 2024 में सत्ता से हटते हुए भारत में शरण लेती हैं। इसके बाद प्रमुख सलाहकार युजुस की अंतरिम सरकार सत्ता की बागडोर संभालती है और फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तोड़ने-मरोड़ने का खेल शुरू हो जाता है। सबसे भरोसेमंद और द्विपक्षी पड़ोसी मित्र देश को दूर करने और दुश्मनों के हो के लगाने का काम होता है। इस दौरान न हिंसा रुकती है और न ही हालात बदलते हैं। इसी के साथ चुनाव की तारीख भी सामने आ जाती है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का अवसर भर नहीं है, बल्कि ये देश की वैचारिक दिशा, लोकतांत्रिक संरचना, संसदीयता और पड़ोसी देशों खासकर भारत से वसंतों की जमीन तय करने वाले निर्णायक मोड़ साबित होगें। कुल 300 सीटों में से 299 सीटों पर मतदान और अजुलाई चार्टर्डरू पर जनमत संग्रह के साथ यह चुनाव हिंसक स्तरों पर महत्वपूर्ण होने वाले है। बावजूद इसके जिस राजनीतिक माहौल में चुनाव कराए जा रहे हैं, उससे इसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर पहले से ही गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल अवांभीनीक की चुनाव लड़ने की अनुमति न दिए जाने की है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली



बहुत महत्वपूर्ण थी और हस्वराजह्म का नारा उन्होंने ही दिया था, जिसे बाद में लोचमन्ने बालगंगाधर तिलक ने अपनाया और हस्वराज्य ने जन्मसिद्ध अधिकार हँस नारा दिया। वेदों का प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ उन्होंने म्हेता लोगों तक पहुँचाने तथा सम्मान के लिए उन्होंने देशभर में भ्रमण किया। जीवनपर्यन्त वेदों, उपनिषदों का पाठ करने वाले स्वामी जी ने पूरी दुनिया का इस ज्ञान से लाभान्वित किया। उनकी किताब हस्त्यात्म्य प्रकाश आज भी दुनियाभर में अनेक लोगों के लिए मार्गदर्शक साहित्य हो रही है। वेदों को सर्वोच्च मानने वाले स्वामी दयानन्द ने वेदों का प्रमाण देते हुए हिन्दू समाज में फैली कुरीतियों और अविद्यावासों का डडकर विरोध किया। जातिवाद, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में उनका योगदान

उल्लेखनीय है, इसीलिए उन्हें हास-न्यासी योद्धाहू भी कहा जाता है। दलित उद्धार तथा स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी उन्होंने कई आन्दोलन किए। हिन्दू धर्म के अलावा इस्लाम तथा ईसाई धर्म में फैली बुराईयों और अंधविश्वासों का भी उन्होंने जोरदार खंडन किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण, धार्मिक कुरीतियों की रोकथाम तथा वैश्विक एकता के प्रति समर्पित कर दिया है। वे आध्यात्मिक क्रांति के संदेशवाहक थे।

स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई के गिरगांव में गुड़ी पड़वा के दिन 10 अप्रैल 1875 को की थी, जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के साथ समूचे विश्व को एकजुट साथ जोड़ना था। आर्य समाज के द्वारा उन्होंने दस मूल्यों के सिद्धांतों पर चलने की सलाह दी। मूर्ति पूजा के अलावा

बांग्लादेश चुनाव बाद तय होगी दोस्ती या दुश्मनी



यह पार्टी बांग्लादेश की राजनीति की केंद्रीय धुरी रही है। ऐसे में उसका चुनाव मैदान से बाहर होना लोकतांत्रिक प्रतियोगिता की आत्मा को कमजोर करता है। अजमाती लीग के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद ने चुनाव को सुनिश्चित बताते हुए निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया को सतह से गढ़ा गया है कि एक विशेष विचारधारा को सत्ता में बनाए रखा जा सके। उन्होंने ऐसे चुनाव का बहिष्कार करने की अपील अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक से कर डाली। यहां कहना गलत भी नहीं होगा कि यदि विपक्ष का एक बड़ा दल ही चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता स्वतः संदिग्ध हो जाती है। बेरहमाले चुनाव हो रहे हैं ऐसे में जीत-हार के दावे भी सामने आ गए हैं। चुनावी मुकामला मुख्तार तारिक रहमान के नेतृत्व वाले बीएनपी गठबंधन और जमात-ए-इस्लामी व नेशनल स्टिंडन पार्टी (एनएसपी) के 11 दलों के गठबंधन के बीच माना जा रहा है। अनुमानित वोट प्रतिशत बताता है, कि मुकाबला कट का है। 12

वर्षों के प्रतिबन्ध के बाद जमात-ए-इस्लामी का चुनावी मैदान में लौटना भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 2008 के बाद पहली बार वह चुनाव लड़ रही है। खुद को मुख्यधारा की राजनीति में स्थापित करने के प्रयास में जमात ने इस बार एक हिंदू उम्मीदवार को टिकट दिया है, हालांकि किसी महिला को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर जमात सुखियां भी बेधर रही है। इस मामले में पार्टी का तर्क है कि महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यह तर्क समावेशी राजनीति की कसौटी पर अधूरा लगता है।

बांग्लादेश के आम चुनाव का एक आयात विदेश नीति भी है। जमात-ए-इस्लामी के नेताओं ने संकेत दिए हैं कि वे सामान्य और मर्यादा के आधार पर विदेश संबंधों को पुनर्निर्माणित करना चाहते हैं। पिछले 16 वर्षों की विदेश नीति को एक देश अर्थात् भारत केन्द्रित बताकर उसकी आलोचना की जा रही है। तीसरा जल बंटवारा, सूझ पर होने वाली घटनाएं और साझा नदियों के पानी का मुद्दा प्रमुख चुनावी विषय बन चुके हैं। यह

जाए। जनता ने सांसदों को नारे लगाने या कार्यवाही बाधित करने के लिए नहीं, बल्कि देश के भविष्य पर गंभीर विमर्श के लिए चुना है। यदि संसद इस अपेक्षा पर खरी नहीं उतरती, तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है।

यह भी तथ्य है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में श्री ओम बिर्ला का संसदीय संचालन अब तक सामान्यतः अनुशासित, कार्यकुशल और नियमसम्मत माना जाता रहा है। उनके कार्यकाल में लोकसभा की कार्यवाही को समग्रदृष्टि दृष्टि से अग्रे बढ़ाने, विधायी कार्यों को प्राथमिकता देने और विभिन्न दलों को साथ लेकर चलने का प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अनेक अवसरों पर उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है तथा संसदीयता के परंपराओं और नियमों के पालन पर बल दिया है। उनकी छवि एक ऐसे अध्यक्ष की रही है जो सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए होशियारी, धैर्य और व्यावहारिक समझ का प्रयोग करते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, संसदीय मर्यादों का आग्रह और संवाद के लिए दरवाजे खुले रखने की प्रवृत्ति को देखते हुए एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति अपने आप में एक त्रासद और चिंताजनक घटना प्रतीत होती है। यह घटना व्यक्ति विशेष से अधिक उस माहौल की ओर संकेत करती है, जहाँ अविश्वास इतना गहरा हो चुका है कि संवाद और विश्वास के पुल कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अंततः यह समय आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जिम्मेदारी स्वीकार करने का है। सत्तापक्ष को यह समझना होगा कि जबतक विपक्ष लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। विपक्ष को यह स्वीकार करना होगा कि विरोध की भी एक मर्याद और रचनात्मकता होती है। और अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पदों को यह स्मरण रखना होगा कि उनकी निष्पक्षता केवल नियमों के पालन से नहीं, बल्कि व्यवहार और अवसर की समानता से भी सिद्ध होती है। यदि संसद को संवाद का मंच बनाए रखने में हम विफल रहते हैं, तो यह केवल एक सत्र या एक सरकार की विफलता नहीं होगी, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक असफलता मानी जाएगी। यही वह बिंदु है जहाँ हर नागरिक, हर जनप्रतिनिधि और हर संस्था को आत्मचिंतन करना होगा, ताकि विकास की राह में विनाश की संभावनाएँ नहीं, बल्कि संवाद, विश्वास और लोकतांत्रिक परिपक्वता का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

वे जाति विवाह, महिलाओं के प्रति असमानता की भावना, मांस के सेवन, पशुओं की बलि देने, मर्ियों में चढ़ावा देने इत्यादि के सख्त खिलाफ थे और इसके लिए उन्होंने लोगों में जागरूकता पैदा करने के अथक प्रयास किए। अपने 59 वर्ष के जीवनकाल में महर्षि दयानंद ने न सिर्फ देश में व्याप्त बुराईयों के खिलाफ लोगों को जागृत किया बल्कि अपने वैदिक ज्ञान से नवीन प्रकाश की भी देशभर में फैलाया। हालांकि कई लोगों ने उनका जमकर विरोध भी किया लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के तार्किक ज्ञान के समक्ष बड़े-बड़े विद्वानों और पंडितों की भी नतमस्तक होना पड़ा। वे अपने जीवन को पुनर्जन, ब्रह्मचर्य, सत्यास तथा कर्म सिद्धांत के चार स्तंभों पर खड़ा मानते थे।

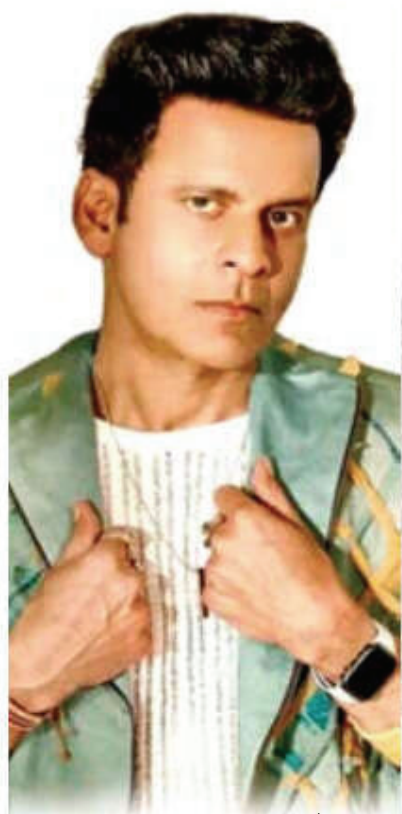
स्वामी दयानंद हिन्दी भाषा के प्रबल समर्थक थे और उनका मत था कि ब्रह्मशरीर से लेकर कन्याकुमारी तक पुरुष देश में एक ही भाषा हिन्दी-बोली जानी चाहिए। मानव शरीर को नश्वर बताते हुए वह कहते थे कि हमें इस शरीर-रक्षा के जरिये केवल एक अस्वर मिला है, स्वयं को साबित करने का कि हमनृपयुक्ताह और ह्यआत्सर्विकवह क्या है? वे कहा करते थे कि शक्ति किमि अलौकिकता या चमत्कारिता के प्रदर्शन के लिए नहीं होती। सभी धर्मों और देशों अयुग्ययियों को वे एक ही ध्वज तले बैठे देखना चाहते थे। दरअसल उनका मानना था कि आपसी लड़ाई का फायदा सदैव तीसरा उठाता है, इसलिए इस भेद को दूर करना आवश्यक है। कर्म करने को लेकर स्वामी जी तर्क देते थे कि काम करने से पहले सोचना बुद्धिमान, काम करते हुए सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। वह कहा करते थे कि दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और तब आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौटकर आएगा। उनका कहना था कि अज्ञानी होना गलत नहीं है लेकिन अज्ञानी बने रहना गलत है।

एषट है कि बांग्लादेश में भारत के साथ संबंध अब निर्विवाद नहीं रहेंगे। यदि नई सरकार भारत के प्रति अधिक कठोर रुख अपनाती है, तो द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है। सुरक्षा कारण बताकर भारत द्वारा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक न भेजना भी इन्हीं संकेतों की ओर इशारा करता है। यह या तो सतर्क दूरी का संकेत है या फिर आंतरिक परिस्थितियों को लेकर एक प्रकार की प्रतीक्षा की नीति। वैसे यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के लिए बांग्लादेश केवल पड़ोसी देश ही नहीं है, बल्कि सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार भी है। सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता, आतंकवाद-रोधी सहयोग और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी इन सभी पर ढाका की राजनीतिक दिशा का सीधा असर पड़ता है। चिंता का विषय यह भी है कि चुनावी विमर्श में वैचारिक ध्रुवीकरण बढ़ता दिख रहा है। यदि कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होती हैं, तो अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदु समुदाय की सुरक्षा और सामाजिक सोहार्द पर प्रसन्नहृदय लग सकते हैं। बांग्लादेश ने पिछले दशक में आर्थिक प्रगति और सामाजिक सुचारुकों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। राजनीतिक अस्थिरता या वैचारिक टकराव इस उपलब्धिक को कमजोर कर सकता है। ऐसे में यह चुनाव केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश के लोकतांत्रिक चरित्र, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और क्षेत्रीय संतुलन की परीक्षा है। नई सरकार यह तय करेगी कि देश सहयोग और संवाद की राह पर चलेगा या टकराव और अविश्वास और मुड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के संबंध इतिहास, भूगोल और साझा संघर्षों से जुड़े हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ढाका में जो भी सत्ता में आए, वह राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्रीय शांति और सहयोग को प्राथमिकता देगा। क्योंकि अंततः स्थिर, समबंधी और संतुलित बांग्लादेश ही पूरे दक्षिण एशिया के हित में है।



विजय सिंह, रामनिवास सांवरिया, सतीश निमोरीय, पीताम्बर सिंह, सुभाष चंद, जितेंद्र सांवरिया, मुकेश सांवरियावाल, रंजंद सांवरिया, धनवीर झांडिया, नेनेंद्र शर्मा, प्राण सुख सैनी, हरप्रदीप यादव, अशोक निमोरीय, अमित सोनी, मनोहर यादव, गजेंद्र सिंह, नितिन यादव, भाणु प्रसाद सोनी, हरीओज जांगिड़, रंजेश यादव, नरफेसिंह यादव, राजेंद्र चौहान, धर्मेन्द्र यादव, मनजनीत सामंथिया, हर्षित गुप्ता, सुरेश कुमार, देवेन्द्र देवीवाल, नवीन, कृष्ण कुमार, बरसीवाल, रमजीत टाडीमिस्त्र, सुनील मुरी, भरत मुंगी समेत अन्य अधिकताओं ने एक-दूसरे को बधाई दी।

मेघवाल समाज के जिलाध्यक्ष त्रिलोक जयपाल सहित बड़ी संख्या में समाजबंधुओं ने इस पहल की सहानुभूति दी। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार का विवाह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बन सकते हैं। इससे मध्यमवर्गीय परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी, ढेरजं धन या जैसी कार्यधियां पर अंकुश लगेगा और युवाओं को सदाग्री वरु उच्च विचार अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। यह सदाग्रीपूर्ण विवाह समाज के लिए एक प्रेरक संदेश बनकर उभरा है, जो दर्शाता है कि वास्तविक सम्मान और खुशहाली धन के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि संस्कार और विचारों की समृद्धि में निहित है।



‘भागम भाग 2’ में हुई मनोज बाजपेयी की एंट्री! गोविंदा को करेंगे रिप्लेस?

बॉलीवुड में इन दिनों पुरानी कल्ट फिल्मों के सीक्वल बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में अब साल 2006 में आई कल्ट कॉमेडी फिल्म ‘भागम भाग’ का सीक्वल भी बनने जा रहा है। फिल्म को लेकर काफी दिनों से चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि फिल्म इस साल प्लोर पर आ जाएगी। इस बीच अब ‘भागम भाग 2’ को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है।

गोविंदा की जगह लेंगे मनोज

एक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘भागम भाग 2’ की कास्ट में एक बड़ा बदलाव किया गया है। सीक्वल में जहां अक्षय कुमार और परेश रावल की वापसी हुई है। वहीं गोविंदा की जगह फिल्म



में मनोज बाजपेयी नजर आ सकते हैं। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म निर्माताओं ने मनोज बाजपेयी को कास्ट कर लिया है। मनोज बाजपेयी फिल्म में गोविंदा की जगह लेंगे। यह खबर हाल ही में सामने आई है। ‘भागम भाग’ में गोविंदा के किरदार को काफी पसंद किया गया था। उनकी कॉमिक टाइमिंग वैसे भी काफी पसंद की जाती है। ऐसे में अब गोविंदा की जगह मनोज बाजपेयी को लेना, कितना कारगर रहेगा ये तो फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अभी तक मेकर्स की ओर से ‘भागम भाग 2’ की कास्ट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

राज शांडिल्य करेंगे निर्देशन

फिल्म को लेकर अभी तक आ रही खबरों के मुताबिक, सीक्वल का निर्देशन राज शांडिल्य करेंगे और इसकी कहानी भी पहचान को लेकर होने वाली गलतफहमी पर आधारित होगी। जबकि ‘भागम भाग’ का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था। फिल्म में मीनाक्षी चौधरी अक्षय कुमार के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आएंगी। जबकि मनोज बाजपेयी के अपोजिट नजर आने वाली हीरोइन की तलाश अभी जारी है। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिल्म की शूटिंग अगले महीने से मुंबई में शुरू होने की खबरें हैं।



अनुभव सिन्हा की इन्वेस्टिव कोर्टरूम ड्रामा फिल्म अस्सी में नजर आएंगी तापसी

तापसी पन्नू निर्देशक अनुभव सिन्हा के साथ आने वाली इन्वेस्टिव कोर्टरूम ड्रामा फिल्म अस्सी में नजर आएंगी। दमदार मोशन पोस्टर से मिले जबरदस्त रिसर्पोन्स के बाद, निर्माताओं ने फिल्म को सीधे दर्शकों तक ले जाने की शुरुआत कर दी है—और इसकी शुरुआत आज जयपुर में एक खास ऑन-ग्राउंड शोकेस से हुई। फिल्म की अनोखी प्रमोशनल स्ट्रेटजी के तहत, तापसी पन्नू ने जयपुर मीडिया के साथ एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहीं टीम ने साथ ही बड़े पर्दे पर अस्सी का ट्रेलर भी दिखाया। अभिनेत्री ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ ट्रेलर देखा, पत्रकारों, फैंस और डिजिटल क्रिएटर्स से सीधे संवाद किया और फिल्म तथा उसके संशक्त विषय पर अपने विचार साझा किए। अस्सी के मोशन पोस्टर ने अपने सख्त टोन और तात्कालिक संदेश के कारण पहले ही काफी उत्सुकता पैदा कर दी थी, जिसने एक हार्ड-हिटिंग सिनेमैटिक अनुभव की मजबूत नींव रखी। जयपुर दौरे ने इस उत्साह को और बढ़ाया, जहां दर्शकों ने फिल्म के तीव्र कोर्टरूम माहौल और सामाजिक संरोकारों से जुड़ी कहानी को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। तेज रफ्तार इन्वेस्टिव थ्रिलर के रूप में पेश की जा रही अस्सी, एक बिल्कुल नए तरह के



कोर्टरूम ड्रामा के जरिए आगे बढ़ती है, जो देश में रोजाना दर्ज होने वाले लगभग अस्सी यौन उत्पीड़न मामलों की भयावह सच्चाई से प्रेरित है। फिल्म को एक अर्जेंट वॉच के तौर पर पोजिशन किया जा रहा है, जो मजबूत महिला नायिकाओं के नेतृत्व में सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानियों के लिए बढ़ती दर्शक रुचि को दर्शाता है। तापसी पन्नू के साथ फिल्म में कनी कुसरुति, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा और मोहम्मद जीशान अय्युब भी अहम भूमिकाओं में हैं। वहीं नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा की विशेष प्रस्तुतियाँ फिल्म की रोमांचक गहराई को और बढ़ाती हैं। गुलशन कुमार और टी-सीरीज प्रस्तुत अस्सी, बेनारस मीडिया वर्क्स के बेनर तले बनी है। फिल्म का निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है और निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अनुभव सिन्हा ने किया है। अस्सी 20 फरवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में विशेष रूप से रिलीज होगी।



सई मांजरेकर ने साझा किया ‘द इंडिया हाउस’ का अनुभव

भारतीय सिनेमा की पैन-इंडिया फिल्मों में काम करना जितना रोमांचक होता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। इस कड़ी में अभिनेत्री सई मांजरेकर इन दिनों अपनी आने वाली पैन-इंडिया पीरियड ड्रामा फिल्म ‘द इंडिया हाउस’ को लेकर काफी बिजी हैं। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में एक साथ शूट की जा रही है। सई का कहना है कि इस तरह की फिल्म में काम करने के लिए कलाकार को हर समय भावनात्मक और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहना पड़ता है। सई मांजरेकर ने कहा, ‘‘द इंडिया हाउस’ मेरे लिए अब तक का अलग अनुभव रहा है। जब एक ही सीन को दो भाषाओं में शूट किया जाता है, तो कलाकार को भाषा की लय, भाव और भावनात्मक गहराई को बारीकी के साथ समझना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही सीन पहले एक भाषा में और तुरंत बाद दूसरी भाषा में करना होता है, जिससे कलाकार को हर पल सतर्क रहना पड़ता है।’ उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह की फिल्मों में अभिनय का तरीका भी थोड़ा बदल जाता है। यहां सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से कहानी को आगे बढ़ाना होता है। हर भाषा की अपनी एक संवेदना होती है और उसी के अनुसार किरदार की भावनाएं भी बदलती हैं। ऐसे में कलाकार को अपने अभिनय को बार-बार ढालना पड़ता है, ताकि किरदार हर भाषा में उतना ही सच्चा लगे।’’ सई ने कहा, ‘‘मेरी पिछली फिल्म ‘मेजर’ की शूटिंग का अनुभव इस फिल्म में काफी काम आया। उस फिल्म से मुझे यह समझने में मदद मिली कि द्विभाषी फिल्मों की शूटिंग

कैसे होती है और कलाकार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि हर प्रोजेक्ट की अपनी अलग पहचान और चुनौतियां होती हैं। ‘द इंडिया हाउस’ की कहानी और उसका ऐतिहासिक संदर्भ इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाता है।’ ‘‘द इंडिया हाउस’ फिल्म में सई मांजरेकर ‘सती’ नाम की महिला का किरदार निभा रही हैं। इस पर सई ने कहा, ‘‘सती का किरदार निभाने के लिए मुझे उस समय के माहौल, सोच और भावनाओं को गहराई से समझना पड़ा। सती बाहर से शांत दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर साहस, दर्द और संघर्ष छिपा है। इन भावनाओं को बिना ज्यादा शब्दों के दर्शकों तक पहुंचाना मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है।’ पैन-इंडिया फिल्मों की खास बात बताते हुए सई ने कहा, ‘‘ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करने का सबसे अच्छा पहलू टीमवर्क होता है। सेट पर अलग-अलग राज्यों और भाषाओं से आए कलाकार और तकनीशियन एक साथ काम करते हैं। सबका लक्ष्य कहानी को ईमानदारी से पर्दे पर उतारना होता है। यह सामूहिक भावना कलाकार को और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है।’’

सई ने अपने सह-कलाकार निखिल सिद्धार्थ, निर्देशक वामसी और पूरी टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘‘सेट पर काम करने का माहौल बेहद सकारात्मक और कहानी पर केंद्रित रहता है। जब निर्देशक और पूरी टीम कहानी को लेकर गंभीर होती है, तो कलाकार भी अपने किरदार में और गहराई से उतर पाता है।’’

आदित्य के साथ हॉरर थ्रिलर बनाएंगे करण जौहर

धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले करण जौहर एक नई हॉरर थ्रिलर फिल्म बनाने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह फिल्म पूरी तरह प्योर हॉरर जॉनर की होगी और इस वक्त कास्टिंग स्ट्रेज में है। इससे पहले करण, कार्तिक आर्यन के साथ क्रिएचर कॉमेडी ‘नागजिला’ और एक क्रिएचर थ्रिलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हालांकि इस हॉरर थ्रिलर में आदित्य रॉय कपूर को लीड



रॉय को लीड कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार, आदित्य ने स्क्रिप्ट पढ़ते ही प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी। यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पर आधारित फिल्म है और धर्मा प्रोडक्शंस को इसके थिएट्रिकल पोटेंशियल पर पुरा भरोसा है। इस फिल्म की शूटिंग मई 2026 से शुरू होने की तैयारी है। एक टॉप टियर फीमेल लीड को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। फिल्म के प्री-प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है।

ऋतिक की ‘कृष 4’ में फाइनल चोपड़ा की एंट्री हुई प्रियंका

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार... ‘प्रियंका को ऋतिक रोशन की सुपरहिट फिल्म ‘कृष 4’ में फीमेल लीड के रूप में फाइनल कर लिया गया है। प्रियंका ने इस फ्रेंचाइज की पिछली दो फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई थी, इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की ओर फोकस किया और अपने पर्सनल लाइफ, खासकर शादी में बिजी हो गई थी। फिल्म ‘वाराणसी’ का शूट पूरा करने के बाद प्रियंका ‘कृष 4’ की शूटिंग शुरू करेंगी। हालांकि अभी मेकर्स या प्रियंका की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ‘कृष 4’ को ऋतिक 700 करोड़ रुपये के बजट पर बनाना चाहते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट भी खुद ऋतिक करेंगे। बता दें कि 2003 में राकेश के निर्देशन में साइंस फिक्शन फिल्म ‘कोई.... मिल गया’ रिलीज हुई। इस फिल्म ने बॉलीवुड को एक नया सुपरहीरो दिया। ‘कोई मिल गया’ के बाद आई ‘कृष’, यह भी सुपरहिट रही। फिर राकेश रोशन ने ‘कृष 3’ के लिए लंबा इंतजार करवाया। 2006 में ‘कृष’ की सफलता के बाद ‘कृष 3’ 2013 में आई। इसमें विवेक ओबेरॉय विलेन बने थे। इस फिल्म के अलावा प्रियंका इन दिनों अपनी फिल्म ‘वाराणसी’ को लेकर भी चर्चा में हैं। इसमें उनके साथ महेश बाबू लीड रोल में दिखाई देंगे। यह एक बड़े बजट की फिल्म होगी।



सुनील शेट्टी ने बेटे अहान के प्रोफेशनलिज्म को लेकर बात की

अहान शेट्टी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस बीच अब अहान शेट्टी की फिल्म ‘सनकी’ के बंद होने की चर्चाएं एक बार फिर से उठी हैं। दरअसल, इस फिल्म के बंद होने की वजह अहान शेट्टी के सपोर्टिंग स्टाफ पर आने वाले अधिक खर्च को बताया गया था। कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया था कि अहान शेट्टी के सहयोगी स्टाफ पर अधिक खर्च आने के कारण मेकर्स ने ‘सनकी’ फिल्म को टंडे बस्ते में डाल दिया। अब इन चर्चाओं पर अहान के पिता व अभिनेता सुनील शेट्टी ने प्रतिक्रिया दी है।

प्रोड्यूसर ने फैलाई अफवाहें

2021 में अहान की डेब्यू फिल्म ‘तड़प’ के रिलीज होने के बाद उनकी अगली फिल्म ‘सनकी’ को अचानक रोक दिया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह फैसला अहान के साथ

आप लोगों के कारण कथित तौर पर हुए खर्चों से बढ़ी चिंताओं के बाद लिया गया है। अब लहरें रेट्रो के साथ बातचीत में अभिनेता सुनील शेट्टी ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने बेटे अहान के प्रोफेशनलिज्म को लेकर भी बात की। सुनील शेट्टी ने कहा कि अहान ने कभी भी अपने साथ आप लोगों को हद से ज्यादा नहीं रखा। ये सब अफवाहें हैं। ये अफवाहें निर्माता की सुविधा के लिए फैलाई गई हैं। अगर निर्माता कहता है कि वह बिल दिखा सकता है, तो मैं देखूंगा। ऐसे में पिता को दखल देना पड़ता है और मैं साफ तौर पर दखल दूंगा। अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए झूठ मत फैलाओ, क्योंकि यह अहान के साथ नाइंसाफी है।

अहान खुद उठाते हैं अपने स्टाफ का खर्च

सुनील शेट्टी ने आगे कहा कि अहान अपने साथ आने वाले लोगों को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। अगर वे उनके साथ आते हैं, तो उनका खर्च वही उठाते हैं। उन्हें इस बात का पूरा एहसास है। जब सुनील शेट्टी घर से खाना-पानी लाते हैं, तो मेरे स्टाफ को कहा गया है कि अगर आप यूनिट का खाना खा रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन अगर आप

बाहर से खाना मंगवाना चाहते हैं, तो बिल मेरे नाम से बनवाएं, निर्माता के नाम से नहीं। मेरा स्टाफ ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए अहान का स्टाफ तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। अहान तो अभी-अभी इंडस्ट्री में आए हैं। यह उनका इंडस्ट्री में जमाने का समय है, इसलिए कोई नखरे नहीं चलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता।

कई रिपोर्ट्स में इन कारणों का भी किया गया जिक्र

कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि साजिद नाडियाडवाला ने शुरू में ‘सनकी’ को आगे बढ़ाया था और प्राइम वीडियो के साथ एक बड़ा डिजिटल सौदा भी किया था। हालांकि, इस सबके बावजूद सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स से कम कमाई के कारण प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। इसके साथ ही कथित तौर पर अहान के सपोर्ट स्टाफ का अत्यधिक खर्च भी इसका कारण बना। लेकिन अब सुनील शेट्टी ने अहान के सपोर्ट स्टाफ के खर्च की बात को झूठा करार दिया है।

अहान शेट्टी ने साल 2021 में आई एक्शन-रोमांटिक फिल्म ‘तड़प’ से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी। हालांकि, इसके बाद लगभग चार

साल से अधिक समय तक वो बड़े पर्दे से दूर रहे। अब इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई ‘बॉर्डर 2’ अहान की दूसरी फिल्म है। फिल्म में उन्होंने नेवी ऑफिसर की भूमिका निभाई है। फिल्म को दर्शकों और क्लिंटक्स की अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। वहीं अहान के काम को भी पसंद किया गया है।



